प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

31.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

प्रश्नकाल

प्रदेश के लोगों को हिमकेयर और आयुष्मान योजना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज विधायक राकेश जम्वाल के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के चार मैडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत हो गई है जिसमें सर्जरी के लिए एक लाख रूपए तक का खर्च आता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मरीज़ों को राहत देने के लिए रोबोटिक सर्जरी पर 70 हज़ार रूपए की सब्सिडी दे रही है। विधायक अनिल शर्मा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में पहले 5 सौ 83 डेयरी सोसायटी पंजीकृत थीं जो पिछले 3 साल में बढ़कर 7 सौ 61 हो गई हैं। उन्होंने बताया कि जायका परियोजना के माध्यम से प्रदेश में कुछ चिलिंग और मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

भाजपा प्रदर्शन

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर बढ़े हुए एंट्री टैक्स को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के वाहन चालकों के संगठनों ने आज रात से सीमाओं पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। एंट्री टैक्स के मुद्दे पर विपक्षी दल भाजपा ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बढ़े हुए एंट्री टैक्स को तुरंत वापिस लेने की सरकार से मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बिना सोचे–समझे फैसले ले रहे हैं जिसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने पैट्रोल–डीज़ल पर लगाए जाने वाले सैस को भी न लगाने की राज्य सरकार से मांग की है।

प्वाइंट ऑफ ऑर्डर

इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि एंट्री टैक्स के विवाद पर वे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रदर्शन की चेतावनी की फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं है और अभी हालात सामान्य हैं।

वित्त आयोग–अनुदान

केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत आठ राज्यों को दो हजार 4 सौ 61 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को करीब 14 करोड़ रूपए की राशि

जारी की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है।

एमओयू

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस हिमाचल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगी, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली ताज़ी सब्जियां, फल, दूध और पनीर सहित अन्य कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों उत्तरी फ्रंटियर कमांडर आई जी मनु महाराज और सेक्टर कमांडर डीआईजी पवन कुमार नेगी के साथ विचार–विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आईटीबीपी को जहां ताजा और उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी वहीं सीमावर्ती गांवों के किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार उपलब्ध होगा।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देशभर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए विकास व कल्याणकारी पहलों संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए पी.एम.जे.वी.के. के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी भी सदन में प्रस्तुत की।

————————————————